



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ३]

शनिवार, फेब्रुवारी १५, २०२०/माघ २६, शके १९४१

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित ४ फरवरी २०२० ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IV OF 2020.

AN ORDINANCE

*further to amend the Maharashtra Municipal Councils,
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965.*

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ सन् २०२०।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर
संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं
सन् १९६५ जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत और औद्योगिक नगरी
को महा. ४०। अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २ में संशोधन। २. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (७) के, उप-खण्ड (दो) में, “के रूप में निर्वाचित हुए” शब्दों को पश्चात् “धारा ५१ के अधीन धारा ५१क-१ख के अनुसरण में परिषद का अध्यक्ष या” शब्द निविष्ट किए जायेंगे :—

सन् १९६५ का महा. ४० में धारा ५१क-१ख का निवेशन। ३. मूल अधिनियम की धारा ५१क-१क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए धारा ५१क-१क का लागू न होना। “५१क-१ख. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, परिषद के आम निर्वाचन और उप-निर्वाचनों के संबंध में, धारा ५१क-१क के उपबंध लागू होने से परिवर्तित हो जायेंगे और प्रत्येक परिषद का अध्यक्ष वह होगा जो धारा ५१ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ५१ के उपबंध लागू होंगे।”।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१क में संशोधन। ४. मूल अधिनियम की धारा ५१क की, उप-धारा (६क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“(६ख) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, परिषद के आम निर्वाचन और उप-निर्वाचन के संबंध में, उप-धारा (६क) के उपबंध लागू होने से परिवर्तित हो जायेंगे और प्रत्येक परिषद का उपाध्यक्ष वह होगा जो धारा ५१ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ५१क के उपबंध लागू होंगे।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५२ में संशोधन। ५. मूल अधिनियम की धारा ५२, की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“(४) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, धारा ५१ के अधीन धारा ५१क-१ख के अनुसरण में, अध्यक्ष की पदावधि की शर्तें उप-धारा (१) में यथा उपबंधित ऐसी होंगी।”।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५ का प्रतिस्थापन। ६. मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान में, निम्न धारा रखा जायेगा, अर्थात् :—

“५५. (१) धारा ५१ के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने की माँग पर कुल पार्षदों की संख्या के आधे से अनिम्न पार्षदों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिये और उसमें ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध कदाचार के आरोप अंतर्विष्ट होंगे और उसे कलक्टर को भेजा जायेगा :

परंतु, ऐसे अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी माँग नहीं भेजी जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन माँग की प्राप्ति पर, कलक्टर, ऐसे आरोपों की जाँच संचालित करेगा और ऐसी जाँच, माँग की प्राप्ति के दिनांक से एक महिने की अवधि के भीतर पूरी की जायेगी ;

परंतु, किसी मामले में जाँच का ऐसा अवधि तीन महिने से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा और यदि जाँच प्रक्रिया अनिवार्य कारणों द्वारा विलंबित होती है तो ऐसे विस्तारित अवधि के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति कलक्टर द्वारा प्राप्त की जायेगी।

(३) कलक्टर, धारा ५५क के अधीन समुचित कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को जाँच के निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

७. मूल अधिनियम की धारा ५८ की उप-धारा (१क) में, “ धारा ५१क १क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को, राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाए, विकास कार्यों के ऐसे प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी ” शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान में, “ धारा ५१ के अधीन धारा ५१क-१ख के अनुसरण में निर्वाचित अध्यक्ष या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को, राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि समय-समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विकास कार्यों के ऐसे प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
५८ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ९३ की, उप-धारा (२), के, खण्ड (ग) के, परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
९३ में संशोधन।

“ परंतु, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकें ऐसी संविदा के लिए, अध्यक्ष की समिति (धारा ५१ के अधीन धारा ५१क-१ख के अनुसरण में निर्वाचित, या, यथास्थिति, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित) और मुख्य अधिकारी उसकी प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ऐसी संविदा को अनुमोदित करेगा। ”।

९. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-१क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की धारा
३४१ख-१ख का
निवेशन।

सन् २०२०
का महा.
अध्या. ४।

“ ३४१ख-१ख महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, नगर पंचायत के आम निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में, धारा ३४१ख-१क के उपबंध लागू होने से परिवर्तित हो जायेंगे और प्रत्येक नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होगा जो धारा ३४१ख-१ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ३४१ख-१ के उपबंध लागू होंगे। ”।

नगर पंचायत
के अध्यक्ष के
निर्वाचन के
लिए धारा
३४१ ख-१ख
का लागू न
होना।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-२ की, उप-धारा (६क) के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की
धारा ३४१ख-२ में
संशोधन।

सन् २०२०
का महा.
अध्या. ४

“(६ख) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, नगर पंचायत के आम निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में, उप-धारा (६क) के उपबंध लागू होने से परिवर्तित हो जायेंगे और प्रत्येक नगर पंचायत का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा ३४१ख-२ के अधीन निर्वाचित किया जायेगा और उसके लिये उक्त धारा ३४१ख-२ के उपबंध लागू होंगे।”

११. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-४ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६५ का
महा. ४० की
धारा ३४१ख-४ में
संशोधन।

सन् २०२०
का महा.
अध्या. ४

(४) “महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, धारा ३४१ख-२ की, उप-धारा (६ख) के अनुसरण में, निर्वाचित उपाध्यक्ष की पदावधि, धारा ३४१ख-२ की उप-धारा (६) में यथा उपबंधित ऐसी होगी।”।

१२. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-५ के, स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन १९६५
का महा.
४० की
धारा
३४१ख-५
का
प्रतिस्थापन।

पार्षदों द्वारा नगर
पंचायत के अध्यक्ष
को हटाना।

“३४१ख-५. (१) धारा ३४१ख-१ के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष हटाए जाने की माँग पर पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनिम्न द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए और उसमें ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध कदाचार के आरोप अंतर्विष्ट होंगे और उसे कलक्टर के पास भेजा जाएगा :

परंतु, ऐसे अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी कोई माँग भेजी नहीं जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन माँग की, प्राप्ति पर, कलक्टर ऐसे आरोपों की जाँच संचालित करेगा और माँग की प्राप्ति के दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसी जाँच पूरी करेगा :

परंतु, किसी मामले में, यदि जाँच प्रक्रिया, अपरिहार्य कारणों द्वारा विलंबित होती है तो जाँच के ऐसी अवधि तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और ऐसे विस्तारीत अवधि के लिए, कलक्टर द्वारा, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

(३) कलक्टर, उसके लिए यथा प्रयुक्त धारा ५५क के अधीन समुचित कार्यवाही करने के लिए सरकार को जाँच के निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।”।

कठिनाई के
निराकरण की
शक्ति।

१३. (१) यदि इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम, के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, मूल अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, नगर परिषद, और **नगर पंचायत** के अध्यक्ष, परिषद, और **नगर पंचायत** के मतदाताओं द्वारा उसके आम निर्वाचन में सीधे निर्वाचित होते हैं।

विद्यमान स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् और नगर परिषद और **नगर पंचायत** का कार्य आसान बनाने की सुनिश्चिति करने की दृष्टी से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों का यथोचित उपांतरण करना इष्टकर समझती है।

२. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश निम्न है,—

(क) यह उपबंध करना कि, नगर परिषद, और **नगर पंचायत** के अध्यक्ष, उनमें से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

(ख) अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में पारस्परिक उत्तरदायित्व और समझदारी को बढ़ावा देना।

(ग) नगरपालिका क्षेत्रों में, विकास क्रियाकलापों की गति को बढ़ावा देना ; और

(घ) आवश्यक पाए जानेवाले अन्य परिणामस्वरूप संशोधनों को कार्यान्वित करना।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है, कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का ४०) में अधिकतर संशोधन करने के सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित २ फरवरी २०२०।

भगत सिंह कोश्यारी,

महाराष्ट्र के राज्यपाल,

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,

सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।